समिति के विचारार्थ विषय

(i) सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रक सिंचाई परियोजनाओं में मौजूदा जल दर ढांचे तथा इमदाद की सीमा की समीक्षा करना।

(ii) निम्न के लिए सुझाव देना :

(क) जल दरें निर्धारित करने के लिए मानदण्ड ;

(ख) किफायती जल दरों के ओ एण्ड एम कम्पोनेंट में लागत वृद्धि के लिए मानदण्ड;

(ग) विभिन्न कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों के लिए फसलवार/क्षेत्रवार जल दरों की आयतनी आपूर्ति के परिवर्तन के लिए मानदंड ;

(घ) किफायती जल दरों की सफल वसुली के लिए क्रियाविधि सहित संगठनात्मक उपाय ; तथा

(ङ) राज्यों द्वारा उपयुक्त सिंचाई जल दरों की उगाही सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन नियंत्रण

(iii) संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही और भूमिगत जल, दोनों के लिए एक युक्तियुक्त जल दर ढांचा विकसित करना।

(iv) विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव के वर्तमान स्तरों की समीक्षा करना।

(v) पूर्ववर्ती समितियों तथा विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए रखरखाव के मानदण्डों की समीक्षा करना।

(vi) विभिन्न राज्यों में विविध सिंचाई प्रणालियों के लिए कर्मचारी स्थापना संबंधी व्यय के लिए कमांड की प्रति हैक्टेयर ऊपरी सीमा नियत करने सहित रखरखाव प्रभार निर्धारित करने के लिए मानदंड सुझाना।

Pending projects of Arunachal Pradesh

2217. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the details of the projects of Arunachal Pradesh pending with the Planning Commission for approval; and

(b) by when these projects are likely to be given approval?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No project of Arunachal Pradesh is pending with Planning Commission for investment approval.

(b) Question does not arise.

Resources to be earmarked for agricultural sector

2218. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the impact of fertilizer price hike on farmers;

(b) whether it is a fact that the Planning Commission is silent on the resources to be earmarked for the agricultural sector; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) To overcome the likely impact of fertilizer price hike the Government has already allowed a higher increase in the procurement prices. Also, the small and marginal farmers will get fertiliser at the earlier prices only. As such, no adverse impact of the fertiliser price hike is anticipated.

(b) and (c) In the formulation of 8th Five Year Plan the Planning Com-